विकास के लिए आर्थिक सुधार जरूरी

केंद्र-राज्य दोनों को वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नयी दिल्ली, 05 नवंबर. वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने की स्थिति में निरंतर सुधार को जरूरी बताते हुए कहा कि कोई भी वित्त मंत्री लोकलुभावन कार्यक्रमों के लिए पैसा बांटने के बाद यह नहीं कह सकता है कि उसके पास विकास योजनाओं के लिए धन नहीं है.

वित्त मंत्री ने इससे पहले अपने व्याख्यान में कहा कि भारत आज अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत की बदौलत दुनिया के सामने सिर उठाकर बात करता है. उन्होंने कहा, आज मैं अपने हित की बात कर रही हूं तो अपनी शक्ति के साथ करती हूं. भारत 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज चौथे स्थान पर है और जल्दी ही तीसरे स्थान पर होगा. भारत की यह आर्थिक ताकत है जिसके बल पर देश वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार या सैन्य शक्ति से सम्पन्न देश आज उस स्थित में नहीं हैं जिस स्थिति में भारत है क्योंकि वे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं.

सीतारमण ने यहां डेलही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) में हीरक जयंती व्याख्यान देने के बाद विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देने के क्रम में कहा कि सरकारें अपनी आय से अधिक खर्च करने के बाद कर्ज लेने को उद्दत होती हैं, पर कर्ज का स्तर नीचे लाने के लिए सरकार ने अब सार्वजनिक कर्ज को सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित हिस्से तक सीमित रखने की दीर्घकालिक वृहद योजना तय की है जिसका केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर पालन करना होगा.

उन्होंने कहा कि सरकारों के रेवड़ी बांट और विकास के लक्ष्यों के बीच विरोधाभास से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, उत्पादक सम्पत्तियों में निवेश करने और रेवड़ी बांटने के बीच विभाजन की हल्की सी रेखा है. मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर कई राज्य मुफ्त की रेवड़ी बांटने और सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध खर्चों के ऊंचे स्तर के कारण संकट में हैं. वित्त मंत्री ने कहा, हमारे लिए, और विकासित भारत के लक्ष्य के लिए यह जरूरी है कि हम हम पूरी सोच समझ के साथ लगातार राजकोषीय सुधारों की राह पर बने रहें और हमारा राजकोषीय प्रबंध विवेकपूर्ण हो. यह हर जिम्मेदार वित्त मंत्री का दायित्व बनता है.

रुपया सात पैसे मजबूत

मुंबई, 05 नवंबर. तीन दिन की कमजोरी के बाद मंगलवार को रुपया सात पैसे मजबूत; डॉलर की बढ़त और बाजार में गिरावट से रही सीमित बढ़त. लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय मुद्रा बाजार में रुपये ने थोड़ी राहत की सांस ली.

अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया सात पैसे की मजबूती के साथ एक डॉलर के मुकाबले 88.70 रुपये पर बंद हुआ. सोमवार को रुपया 6.50 पैसे कमजोर होकर 88.77 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. दिन के कारोबार के दौरान भारतीय मुद्रा ने 88.55 रुपये प्रति डॉलर पर मजबूत शुरुआत की और सत्र के बीच में 88.28 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन बाद में डॉलर की बढ़ती मांग और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के कारण यह लाभ सीमित रह गया.

व्यापार वार्ता 'बहुत अच्छी' चल रही है : गोयल

भारत-अमेरिका के बीच 'पहले चरण' के समझौते पर सहमति करीब

पांच दौर की वार्ता पूरी, 2025 के अंत तक हस्ताक्षर का लक्ष्य

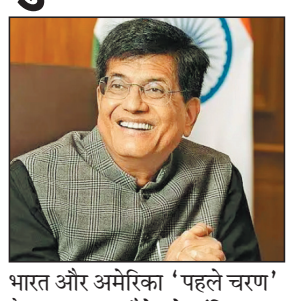

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), 5 नवंबर. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि बातचीत 'बहुत अच्छे स्तर' पर चल रही है, हालांकि कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दों के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है.

गोयल ने कहा, 'बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है. कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें समय लगता है.' हाल ही में एक सरकारी अधिकारी ने भी बताया था कि भारत और अमेरिका 'पहले चरण' के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं. दोनों देशों के बीच अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और फिलहाल समझौते की भाषा को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

23 अक्टूबर को दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच वर्चुअल चर्चा हुई थी. मार्च से अब तक इस समझौते के पहले चरण को लेकर पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है. इसे वर्ष 2025 के अंत तक हस्ताक्षरित करने का लक्ष्य रखा गया है. फरवरी में प्रस्तावित इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था. ट्रंप प्रशासन ने यह कदम भारत के रूस से तेल आयात जारी रखने के चलते उठाया था. दोनों देशों के बीच यह व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है, जिससे भविष्य में व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की संभावना है.

भारत ने जारी किए एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश

'एआई गवर्नेंस के सप्त सूत्र' में ट्रस्ट, निष्पक्षता और जवाबदेही पर जोर

नवाचार और सुरक्षा के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार

नई दिल्ली, 5 नवंबर. देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए.

इनका मुख्य लक्ष्य सभी क्षेत्रों में एक सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम की नींव रखना है. यह फ्रेमवर्क नवाचार और जवाबदेही में संतुलन सुनिश्चित करेगा.

'हानि न पहुंचाना' मुख्य सिद्धांत- भारत के एआई दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत 'हानि न पहुंचाना' है. यह फ्रेमवर्क सात मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें 'एआई गवर्नेंस के सप्त सूत्र' कहा गया है. इनमें ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, और सेफ्टी, रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी शामिल हैं. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने जोर दिया कि भारतीय फ्रेमवर्क लचीले नियामक वातावरण के भीतर नवाचार सैंडबॉक्स और जोखिम शमन तंत्रों को संयोजित करेगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा से समझौता किए बिना एआई नवाचार फले-फूले.

सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि यह दृष्टिकोण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निहित है, जो भारत को सुरक्षित एआई अपनाने में वैश्विक उदाहरण बनाएगा .दस्तावेज में एक व्यापक कार्य योजना भी है, जिसमें अल्पकालिक से दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं. इन उपायों में भारत-विशिष्ट एआई जोखिम फ्रेमवर्क, घटना रिपोर्टिंग प्रणाली, दायित्व व्यवस्था बनाना और उभरती एआई प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक सैंडबॉक्स की शुरुआत करना शामिल है.

महाराष्ट्र ने स्टारलिंक संग मिलाया हाथ

मुंबई,05 नवंबर. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को उद्योगपति एलन मस्क के भारत स्थित उपग्रह संचार उद्यम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लि. के साथ उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की. इस तरह, यह अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है.

सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र को गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे 'दूरदराज और वंचित क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों' में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने को लेकर स्टारलिंक के साथ सहयोग करने वाला पहला राज्य बनाता है.

मस्क की स्टारलिंक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक संचार उपग्रह हैं.

फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि कंपनी भारत आ रही है और महाराष्ट्र के साथ साझेदारी कर रही है.''

वेकोलि में सर्टिफिकेट कैम्पेन का शुभारंभ

नागपुर, 5 नवम्बर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैम्पेन 4.0 का शुभारंभ मंगलवार को वेकोलि मुख्यालय में सीएमडी जेपी द्विवेदी द्वारा किया गया.

इस अवसर पर द्विवेदी ने कहा कि यह अभियान वेकोलि की डिजिटल सशक्तिकरण यात्रा का महत्वपूर्ण चरण है. इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मियों को सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह पहल 'ईज ऑफ लिविंग' को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

निदेशक (कार्मिक) डॉ. हेमंत शरद पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनरों के लिए अत्यंत उपयोगी पहल है, जो उनके कल्याण के प्रति वेकोलि की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. कार्यक्रम की शुरुआत महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध/पेंशन) पी नरेंद्र कुमार के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने अभियान के उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी दी.

इस दौरान रीजनल कमिश्नर-1, सीएमपीएफओ नागपुर क्षेत्र शशांक रायजादा ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला. वहीं सीएमपीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदस्य अशिष मूर्ति ने अभियान की सफलता की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) विक्रम घोष, निदेशक (तकनीकी - संचालन/ परियोजना एवं योजना) आनंदजी प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य, विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मी उपस्थित रहे. आयोजन में वेकोलि पेंशन विभाग की प्रमुख भूमिका रही.

अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 29 प्रतिशत बढ़कर 3,120 करोड़

अहमदाबाद, 05 नवंबर. अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 3,120 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक है. कंपनी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी. इसके अनुसार तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 30 प्रतिशत बढ़कर 9,167 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का परिचालन लाभ 27 फीसदी बढ़कर 5,550 करोड़ रुपये हो गया. निदेशक मंडल ने अडानी पोर्ट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई अडानी हार्बर सर्विसेज के एपीएसईजेड में विलय की योजना को भी मंजूरी प्रदान की.

पेटीएम का फोकस वफादार ग्राहकों पर

स्वर्ण सिक्के' कार्यक्रम से हर भुगतान पर डिजिटल सोने का इनाम.

ग्राहकों के लिए रोज़मर्रा के लेन-देन से धन सृजन का अवसर.

नई दिल्ली, 5 नवंबर. देश की प्रमुख पूर्ण-समग्र भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम (वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) अब उच्च गुणवत्ता वाले वफादार ग्राहक आधार के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही की आय वार्ता के दौरान बताया कि अभिनव 'स्वर्ण सिक्के' कार्यक्रम इसका मुख्य हिस्सा है. यह पहल ग्राहकों के दैनिक लेन-देन को डिजिटल स्वर्ण में निवेश के माध्यम से धन सृजन के अवसर में बदल देती है, जिससे जिम्मेदार वित्तीय आदतों को बढ़ावा मिलता है. उन्होंने कहा कि जो लोग पारस्परिक निधि की ओर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए सोने में निवेश पसंदीदा विकल्प बन रहा है.

तिमाही नतीजों से रणनीति को मिली मजबूती- इस रणनीति को कंपनी के मजबूत वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों से मजबूती मिली है:परिचालन राजस्व साल-दर-साल 24 फीसदी बढ़कर 2,061 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने लगातार दूसरा कर पश्चात लाभ 211 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से 71 फीसदी अधिक है. यह वृद्धि ग्राहकों के बीच भुगतान में बढ़ोतरी और वित्तीय सेवाओं के वितरण में विस्तार के कारण हुई है.

सोने के रिकॉर्ड दामों के बीच भारत को स्वर्ण नीति की जरूरत

नई दिल्ली. सोने की कीमतों में भारी उछाल के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने कहा है कि भारत जैसे बड़े स्वर्ण बाजार के लिए अब एक व्यापक राष्ट्रीय स्वर्ण नीति की आवश्यकता है. रिपोर्ट 'कमिंग ऑफ (ए टर्बुलेंट) एज: द ग्रेट ग्लोबल गोल्ड रश' में बताया गया है कि भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण वर्ष 2025 में अब तक सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है.

भारत में भी माइक्रोसॉफ्ट करेगा लोकल डेटा प्रोसेसिंग

नई दिल्ली, 5 नवंबर. दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह अपने कृत्रिम मेधा आधारित टूल 'माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट' के लिए 2026 तक भारत सहित 15 देशों में स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग सुविधा शुरू करेगी.

कंपनी का यह कदम डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट एक एआई-सक्षम डिजिटल सहायक है, जो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और टीम्स जैसे अनुप्रयोगों में एकीकृत है. यह उपयोगकर्ताओं के निर्देशों पर सामग्री तैयार करने, डेटा विश्लेषण, ईमेल या रिपोर्ट लिखने जैसे कार्य करता है. कंपनी के अनुसार, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ब्रिटेन के ग्राहकों को 2025 के अंत तक यह विकल्प मिलेगा कि उनके कोपायलट टूल से जुड़ा डेटा उन्हीं के देश में स्थित डेटा केंद्रों में प्रसंस्कृत किया जाए.

मोदी ने पकड़ी असली नब्ज

चल दी सबसे तगड़ी चाल, चित हो जाएंगे राहुल-तेजस्वी

सहरसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार के तहत सहरसा में एक चुनावी रैली में बिहार के पहली बार वोट देने वालों को संबोधित किया था. उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपना पहला वोट बर्बाद न करें. उस गठबंधन को वोट दें जिसकी सरकार बनने की संभावना हो.

इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. आपका वोट एनडीए को मज़बूत करने में इस्तेमाल होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कई युवा बेटे-बेटियां पहली बार वोट दे रहे हैं. जब उन्होंने पहली बार वोट डाला, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका वोट बेकार न जाए. वे हवा का रुख़ देखते और फिर वोट देते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके वोट से सरकार बने. वे इसमें सफल रहे. वे आपसे भी पहली बार वोट देने का आग्रह करते हैं. राज्य में एनडीए की सरकार बनने वाली है. इसलिए मैं पहली बार वोट देने वाले सभी युवा बेटे-बेटियों से आग्रह करता हूं कि वे हमें शक्ति दें. आपका वोट एक विकसित बिहार के लिए होना चाहिए. बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है. इसलिए उन्होंने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का आग्रह किया.

क्यों तगड़ा है पीएम का यह दांव?

पीएम मोदी का ये दांव बिहार में एनडीए के को फायदा तो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है. युव वोटरों पर अगर पीएम की मुहिम का असर हुआ तो कहानी कुछ और हो जाएगी. क्योंकि बिहार में इस बार 14 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे. हर सीट पर औसतन 5 हजार 7 सौ फर्स्ट टाइम वोटर है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है.

और क्या बोले पीएम?

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का युवा बिहार का काम करे और राज्य का नाम करे, यह हमारा स्वप्न है. पिछले सालों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है. इस रफ्तार को और तेज करना है. सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया हर साल बाढ़ से परेशान होते थे, पर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया. एनडीए सरकार ने कोसी की बाढ़ से बचाने के लिए कई काम किए. बाढ़ से मुक्ति के लिए 11 हजार करोड़ की परियोजना बन चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बाढ़ के दूरगामी समाधान पर काम कर रही है. कोसी और मेची को जोड़ा जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. साथ ही मछली पालकों और मखाना किसानों को भी बहुत फायदा होगा. मेरा सपना है कि दुनिया के कोने-कोने में मखाना को वहां के खानपान में पहुंचाना है. पीएम मोदी ने कहा कि मछली उत्पादन प्रोत्साहन के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर बजट दिया.

अनंत गए जेल, ललन ने पकड़ा मैदान

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है. दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद सबकी निगाहें मोकामा पर टिकी हैं. प्रशासन और चुनाव आयोग ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और एनडीए के नेता भी मोकामा में काफी सक्रिय हो गए हैं.

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद, जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा की कमान संभाली. सोमवार को चुनाव प्रचार कर रहे ललन सिंह ने कहा कि कानून निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, लेकिन मोकामा की घटना एक साजिश है जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है.

हमने किया कानून का सम्मान- ललन सिंह ने पंडाकर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत पहुंचीं और जांच की. तुरंत कार्रवाई की गई. सुशासन की सरकार ने ईमानदारी से काम किया. हमने कानून के शासन का सम्मान किया. इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि आज अनंत सिंह यहां नहीं हैं. ऐसे में मैंने चुनाव की कमान संभाली है. लेकिन जो हुआ उसमें एक बड़ी साजिश है. यह घटना अचानक नहीं हुई. यह एक साजिश थी.

पुलिस जांच कर रही है. पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा. अनंत सिंह ने कहा कि अनंत सिंह के रूप में चुनाव लड़ना सबकी ज़िम्मेदारी है. सबको पता होना चाहिए कि जब वो नहीं थे, तब हमारी ज़िम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वो नहीं हैं तो हमने मोकामा चुनाव की कमान संभाल ली. आप भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें.

उमर की मुश्किल बढ़ रही है

जम्मू. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किल बढ़ रही है. राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट हारने के बाद उनके ऊपर एक तरफ तो भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगे तो दूसरी ओर कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठा.

ऊपर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेताओं यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के ऊपर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से किया वादा तोड़ने का आरोप भी लगा. इस बीच राज्य की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. 11 नवंबर को बडगाम और नागरोटा सीट पर उपचुनाव होगा.

एक सीट उमर के इस्तीफे से खाली हुई थी तो दूसरी सीट भाजपा के देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली हुई है. इन दोनों सीटों का उपचुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा के साथ साथ आगे की राजनीति का मामला भी है. उधर कांग्रेस के नाराज होने की खबर है.

विशेष | **महाराष्ट्र निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदाता सूची पर सियासी संग्राम**

'सूची वही, नेता बदले!'

मुंबई. स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही अब पक्ष व विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गयी है. विपक्षी जहां वोट चोरी के आरोप लगाते हुए यह मांग कर रहे हैं कि बिना मतदाता सूची में सुधार किए चुनाव नहीं लिए जाएं वहीं सत्ताधारी यह कहकर विपक्ष को घेर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस सूची पर चुनाव हुए और उनके उम्मीदवार चुनकर भी आए, उसी सूची पर यह चुनाव हो रहा है तो फिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है.

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ होने वाले चुनाव की घोषणा पर आनंद व्यक्त करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने तो यह आरक्षण ही समाप्त कर दिया था लेकिन शिंदे-फडणवीस-पवार की महायुति सरकार ने इसे फिर से बहाल किया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का झूठा आरोप विपक्ष लगा रहा है. जिन सूचियों पर महाविकास आघाड़ी के सांसद चुने गए वही सूचियां अब नगरपालिका चुनावों के लिए भी हैं.

साबित किया तो 1,000 का इनाम- जब आप जीते तब लिस्ट सही थी और अब गलत है. रोहित पवार के चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव के आरोप पर उन्होंने पलटवार किया कि रोहित पवार साबित करें कि जिस मतदाता सूची पर वे जीते थे और अब की सूची में फर्क है. यदि साबित कर दें तो उन्हें 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा. सूची वही है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.

इधर, विधानसभा में कांग्रेस पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि भाजपा को इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव कई चरणों में अलग-अलग करवाना है, ताकि वह यंत्रणा का दुरुपयोग कर सके. उन्होंने कहा कि मनपा व जिला परिषद के चुनाव एक साथ लेने की जरूरत है लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसे यंत्रणा का दुरुपयोग करना है, इसलिए अलग-अलग चरणों में चुनाव लेने का दांव है.

सत्ता के दबाव में आयोग : देशमुख

राकां नेता व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां हैं. इसमें सुधार के लिए सभी विपक्षी दलों ने मुंबई में सत्य का मोर्चा निकालकर चुनाव आयोग को निवेदन दिया. सूची स्वच्छ कर निकाय चुनाव लेने की मांग की लेकिन बावजूद इसके आयोग ने नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में है. उसे पहले सूची में पूरी तरह सुधार लेना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए आयोग काम करता नजर आ रहा है. बैलेट पर चुनाव की मांग को भी दरकिनार कर दिया गया है.